रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समय समय पर निर्धारित वेतनमान पर निर्धारित अर्हता प्राप्त रेलवे सेवा कर चुके सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति उपरांत मानार्थ पास दिए जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ). सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को मानार्थ पास दिये जाने पर विचार किया गया था । लेकिन, इसे निःशुल्क यात्रा सुविधाओं का अति उदारीकृत होने के कारण न्यायोचित नहीं ठहराया गया ।

### बिहार में रेल लाइनें

4352. श्री शिबू सोरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना जिले में नयी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान से किस स्थान तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोफैक्ट्री के लिए जिन लोगों की भूमि अर्जित की गयी थी उनको पूरा मुआवजा दे दिया गया है और यदि हां, तो किस दर पर;

(घ) क्या उनको अर्जित भूमि के बदले उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है; और

(ङ) इस समय चित्तरंजन लोको फैक्ट्री में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). पूर्व रेलवे ने रांची रोड हज़ारीबाग टाउन–कोडरमा-गिरिडीह एक नयी बड़ी



लाइन के रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया था और उसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1980 में रेल मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है । इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इसके मूल्यांकन के बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

मन्दारहिल-[illegible] (65 कि०मी०)

पूर्व रेलवे ने इस रेल संपर्क के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है । क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट के शीघ्र ही रेल मंत्रालय में प्राप्त हो जाने की संभावना है । रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर इस मामले पर आगे जांच की जायेगी ।

(ग) जी हां, भूमि के मालिकों को भुगतान करने के लिये पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों को भूमि की लागत की पूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया था ।

(घ) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के निर्माण के समय वहां के स्थानीय/विस्थापित व्यक्तियों को नियोजित करने के संबंध में प्राथमिकता देने की नीति थी ।

(ङ) आदिवासियों के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते । बहरहाल, सफाईवालों में से 302 कर्मचारी अनुसूचित जाति के और 73 अनुसूचित जनजाति के हैं । अन्य कोटियों में अनुसूचित जनजाति के 960 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

### Cases referred by C.G.H.S. Dispensaries to Safdarjung Hospital

4353. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in the CGHS Wing of the Safdarjung hospital, only patients having recommendations or acquaintance

with the doctors are attended to and others either do not get their turn or are simply put off;

(b) whether it is also a fact that cases referred by the CGHS dispensaries to Safdarjung Hospital are either discouraged by the doctors there or are not properly examined with the result the patients have to face a great embarrassment in going to the hospital again and again;

(c) if so, whether Government propose to make surprise checks periodically to set the matters right; and

(d) if not, what steps are envisaged to help the patients to get proper treatment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b). Government is not aware of any such complaints.

(c) Occassional surprised visits are made by the concerned authorities

(d) Does not arise.

**Cashiers and Assistant Cashiers of D.T.C.**

4354. SHRI EBRAHIM SULEIMAN SAIT: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the discontentment among the staff of D.T.C. in category of Cashiers and Assistant Cashiers;

(b) whether recommendations of the Third Pay Commission have not yet been implemented in case of Cashiers and Assistant Cashiers in D.T.C.;

(c) if so, how many persons are suffering monetary losses in this category since the presentation of Third Pay Commission's Report;

(d) the reasons for not implementing the recommendations so far and the steps Government propose to protect the interest of this category in D.T.C.; and

(e) the total estimated amount to be given to these employees in the form of arrears and the time likely to be taken in this process?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Before the Third Pay Commission Cashiers and Assistant Cashiers were in the scales applicable to Senior Clerks and Junior Clerks plus special pay Rs. 40 and Rs. 25 respectively. Their pay was duly fixed according to Government rules based on the recommendation contained in Third Pay Commission Report alongwith the pay of other employees w.e.f. 1-1-1973 in corresponding scale of this category plus special pay of Rs. 55 and Rs. 40 respectively.

(c) No one is suffering monetary loss as their pay has already been fixed in accordance with the rules consequent to Third Pay Commission recommendations.

(d) Does not arise, as their pay has already been fixed in the revised scales.

(e) Does not arise.

**Medically decategorised casual labourers**

4355. SHRI S. A. DORAI SEBASTIAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Southern Railway Authorities are not implementing the Railway Board's directive with regard to alternative jobs for medically decategorised casual labourers;

(b) how many cases are pending in this category from 1977;

(c) whether it is also the fact that large number of vacancies have been